

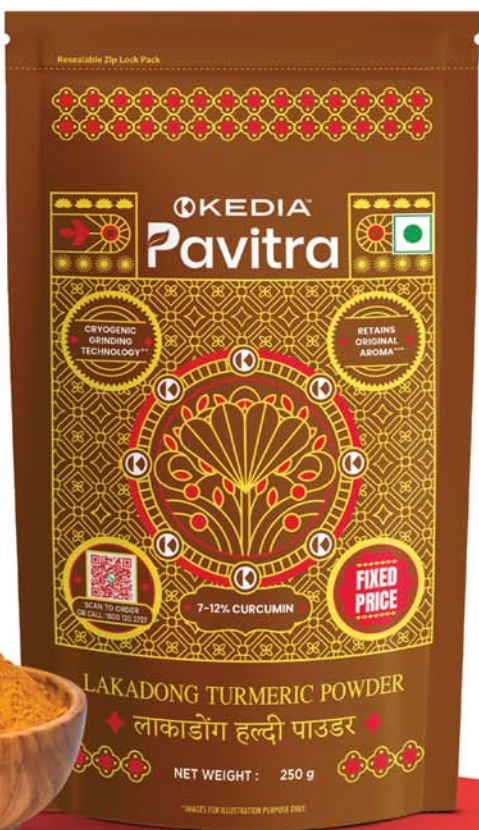
आन्दोलन अशुद्ध के विरुद्ध

KEDIA™ Pavitra

LAUNCHING TODAY

7 - 12% CURCUMIN

लाकाडोंग हल्दी पाउडर | 250 g MRP ₹ 250



DOUBLE PARROT
SABUT DHANIA SE BANA

धनिया पाउडर | 250 g MRP ₹ 100



50,000 + SHU TEEKHAPAN / PUNGENCY

मिर्ची पाउडर | 250 g MRP ₹ 150



MUST TRY OUR:



देशी गेहूँ
10 kg MRP ₹ 450

शरबती सुपीरियर आटा
5 kg MRP ₹ 350

सूजी
500 g MRP ₹ 40

गेहूँ दलिया
500 g MRP ₹ 40

बेसन
500 g MRP ₹ 70

देशी चक्की आटा
5 kg MRP ₹ 250

शरबती गेहूँ
10 kg MRP ₹ 650

COMING SOON:

दाल | चावल | कुकिंग ऑयल | ड्राई फ्रूट्स | चाय

ORDER
ON WEBSITE



ORDER
ON APP



ORDER ON CALL 1800 120 2727

ORDER
ON WHATSAPP



T&C Apply.

ट्रंप ने दवाओं के आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया, एक अक्टूबर से लागू होगा

ट्रंप के इस फैसले से भारतीय फार्मा उद्योग प्रभावित होंगे, जिनका 45 प्रतिशत बिज़नैस अमेरिका के साथ है

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 सितंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की कि 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं के आयात पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ (शुल्क) लगाया जाएगा। भारत की फार्मास्यूटिकल्स (दवा) इंडस्ट्री, जो अमेरिका के साथ व्यापार पर अत्यधिक निर्भर है, इस फैसले से गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।
ट्रंप ने "दुध सोशल" पर कहा, "1 अक्टूबर 2025 से, हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल उत्पाद पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे, जब तक कि संबंधित कंपनी अमेरिका में अपनी फार्मा मैनुफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण नहीं कर रही हो।

- ट्रंप ने घोषणा की है कि इस टैरिफ वृद्धि से उन फार्मा कंपनियों को राहत मिलेगी, जो अमेरिका में ही मैनुफैक्चरिंग केन्द्र बनाने की तैयारी कर रही हैं।
- अमेरिका, भारत के फार्मा उद्योग का सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल फार्मा एक्सपोर्ट का 31 प्रतिशत अमेरिका को हुआ था और इस वर्ष 2025 की पहली छमाही में 3.7 अरब डॉलर का फार्मा निर्यात हो चुका है।
- ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फैसले की जानकारी दी, साथ ही किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटीज़ और फर्नीचर पर भी टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की।
- ट्रंप टैरिफ वृद्धि का कोई वैध कारण नहीं बता सके, पर उन्होंने कहा, देश की सुरक्षा के लिए टैक्स वृद्धि जरूरी है।

अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कहा कि ये टैक्स "राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों" से आवश्यक है।
अमेरिका भारत के फार्मास्यूटिकल उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के कुल 27.9 बिलियन (लगभग 2.47 लाख करोड़) मूल्य के दवा निर्यात में से 31 प्रतिशत या 8.7 बिलियन डॉलर (77,138 करोड़) अमेरिका को भेजे गए थे। वहीं 2025 के पहले 6 महीनों में ही भारत ने अमेरिका को 3.7 बिलियन डॉलर (32,505 करोड़) के फार्मा उत्पाद भेजे हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका में उपयोग होने वाली 45 प्रतिशत से अधिक जैनरिक और 15 प्रतिशत बायोसिमिलर दवाएं भारत से भेजी जाती हैं। रेड्डीज़, ऑरिन्डो फार्मा, ज़ायडस लाइफसाइंसेज, सन फार्मा और ग्लैड फार्मा जैसी कंपनियां अपनी कुल आय का 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अमेरिकी बाजार से कमाती हैं। हालांकि नई अमेरिकी टैरिफ नीति मुख्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाए गए ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं को लक्ष्य (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रॉनल्ड रीगन के फॉर्मूले को दोहरा रहे हैं मोदी

पूर्व राष्ट्रपति रॉनल्ड रीगन ने सेल्स टैक्स में भारी कटौती कर जनता को काफी रकम उपलब्ध कराई, खर्चा करने के लिए

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 सितंबर। सरकार यह दिखाना चाहती है कि वह जनता के हित में काम कर रही है और लाभ लोगों को दे रही है। यही सरकार पहले ही आगकर्म में 12 लाख रुपये सालाना तक की छूट देकर जनता को बड़ा तोहफा दे चुकी है। इन दोनों रियायतों को मिलाकर लोगों के हाथों में लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपये बचेगे और यह लाभ त्योहार के इस सीजन में उनकी खरीददारी की क्षमता बढ़ाएगा। यह कोई नया आर्थिक प्रयोग नहीं, बल्कि जानी मानी आर्थिक रणनीति है, जिसे पहले भी कई बार आजमाया जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति रॉनल्ड रीगन ने बड़े पैमाने पर टैक्स कटौती की थी और उम्मीद की थी कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहने से

- इससे उस समय अमेरिका में "डिमांड" में भारी वृद्धि हुई, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा और इन्वैस्टमेंट बढ़ा इण्डस्ट्री में।
- मोदी ने भी 12 लाख करोड़ रुपए की आय को इनकम टैक्स फ्री करके जनता के हाथ में पैसा दिया तथा जीएसटी भी कम किया, जिससे रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों की कीमत भी काफी घटी।
- इसके साथ, अमेरिका द्वारा खड़ी की गई टैरिफ की दीवार के कारण, अमेरिका के मार्केट के लिए बनी वस्तुएं आगे नहीं खिसक रही थीं तथा कारखानों के गोदामों में फिनिशड गुड्स भरे हुए थे। अतः कंपनियों को भारी मदद मिली, अपने रूके हुए सामान से भारत के डॉमेस्टिक बाज़ार की "डिमांड" पूरी करने में।

मांग बढ़ेगी और पूरी अर्थव्यवस्था में निवेश व उत्पादन का चक्र तेज होगा। यह प्रयोग अमेरिका में सफल रहा और

मांग, उत्पादन और निवेश का संकारात्मक चक्र बना। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मनमोहन सिंह के नाम पर कांग्रेस मुख्यालय में पुस्तकालय खुला

नयी दिल्ली, 26 सितंबर। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी तथा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को यहां पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नाम पर अनुसंधान केन्द्र और पुस्तकालय का उद्घाटन

- सोनिया गांधी और खड्गो ने अनुसंधान केन्द्र व पुस्तकालय का उद्घाटन किया।
- किया। इसका नाम डॉ. मनमोहन सिंह अनुसंधान केन्द्र और पुस्तकालय रखा गया है। यह केन्द्र कांग्रेस के नये मुख्यालय इंदिरा भवन में स्थापित किया गया है। इस केन्द्र पर डॉ. सिंह की पुस्तकें, उनके लेख और भाषणों के संकलन रखे गये हैं।
इस मौके पर डॉ. सिंह की पत्नी गुरशरण कौर, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जस्टिस एस.पी. शर्मा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने

जयपुर, 26 सितम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया कि 27 सितंबर को मौजूदा सीजे के आर

- जस्टिस शर्मा का रिटायरमेंट 26 सितंबर 2026 को होगा।

श्रीराम के सेवानिवृत्त होने के कारण जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया जाता है।
जस्टिस एसपी शर्मा का जन्म 27 सितंबर, 1964 को हुआ था। एलएलबी करने के बाद उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत करना आरंभ किया। उन्हें 16 नवंबर, 2016 को हाईकोर्ट में वकील कोर्ट से न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके बाद जनवरी, 2022 में पटना हाईकोर्ट में उनका तबादला किया गया। जहां से उन्हें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भेजा गया। इसके बाद गत 14 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला किया गया था। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाकिस्तान ने फिर दोहराया, ट्रंप ने रुकवाया था भारत-पाक युद्ध

पाक प्र.मंत्री शहबाज़ शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका यात्रा पर जारी अधिकृत बयान में ट्रंप के दावे का समर्थन किया

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 सितम्बर। क्या पाकिस्तान ने यह स्वीकार कर लिया है कि अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ संघर्षविराम सुनिश्चित करने में उसकी मदद की थी? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत के विवरण से संकेत मिलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने संघर्षविराम शुरू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
भारत ने कई बार इन दावों का खंडन किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उस संघर्षविराम में कोई भूमिका निभाई थी, जो अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले (जिसमें

- पाकिस्तानी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने भारत-पाक सीज़फायर करवाने के लिए ट्रंप के साहसिक व निर्णायक नेतृत्व की प्रशंसा की। यह बात एक तरह से पाकिस्तान की स्वीकारोक्ति है कि ट्रंप ने सीज़फायर करवाया था।
- हालांकि, भारत ने बार-बार कहा है कि सीज़फायर में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है। भारत ने कहा कि 22 अप्रैल (पहलगाम) अटैंक से लेकर 17 जून (सीज़फायर घोषणा) तक ट्रंप और मोदी के बीच फोन पर कोई बात नहीं हुई थी।

26 पर्यटक मारे गए थे) के बाद, पाकिस्तान में आतंकी और सैन्य ढांचे पर की गई एयरस्ट्राइक्स के बाद लागू हुआ था।
लेकिन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी पाकिस्तान के नेताओं की तरह ही दावा

किया है कि वे भी एक कारण रहे थे, जिसकी वजह से दोनों परमाणु-शक्ति संपन्न पड़ोसी देश संघर्षविराम पर सहमत हुए और तनाव को बढ़ने से रोका गया। पाकिस्तानी बयान में कहा गया: "प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज़ शरीफ़

और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान-भारत संघर्षविराम को सुविधाजनक बनाने में राष्ट्रपति ट्रंप के साहसिक, निर्णायक और दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की और गाज़ा में संघर्ष को तुरंत समाप्त करने तथा मध्य पूर्व में शांति बहाल करने के प्रयासों के तहत, मुस्लिम जगत के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित करने की उनकी पहल की प्रशंसा की।"
बयान में आगे कहा गया: "नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की, जिसमें प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश को आमंत्रित किया और सुरक्षा तथा खुफिया सहयोग को और बढ़ाने की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जस्टिस सौमेन सेन मेघायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

नयी दिल्ली, 26 सितंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।

- वे वर्तमान में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं।

केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई।
अधिसूचना में कहा गया है, "राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।"

आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपना काम काज “ऑफिस सुईट ज़ोहो” पर शिफ्ट किया

जैसा कि विदित ही है, ज़ोहो कॉर्पोरेशन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिक है, जो कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और वैंब आधारित बिज़नेस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह अपील कि भारतीय लोग "स्वदेशी टैक" को अपनाएँ, तकनीक में आत्मनिर्भरता की बहस को दोबारा तेज कर रही है। आत्मनिर्भर भारत की बड़ी सोच के हिस्से के रूप में पेश की गई यह पहल विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करने और भारत को नवाचार का वैश्विक केन्द्र बनाने का लक्ष्य रखती है।
स्वदेशी टैक का यह प्रयोग पूरे देश में एक जन आंदोलन बनेगा या सिर्फ

प्रतीकात्मक कदम रह जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि चुनौतियों को कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से निपटारा जाता है। केवल नीतिगत मदद, नवाचार और बाज़ार में स्वीकार्यता का मेल ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि स्वदेशी टैक भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का ठोस आधार बने।
सरकार ने इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नीतिगत कदमों के साथ प्रतीकात्मक काम भी किए हैं। केन्द्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का भारतीय ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट ज़ोहो का उपयोग शुरू करना घरेलू विकल्पों

- भारत सरकार की विदेशी, अमेरिकी आदि कंपनियों पर निर्भरता कम करने की दृष्टि से "स्वदेशी टैक्नॉलजी को देश में पनपाने की मुहिम ही शायद एक रास्ता है, विदेशी सरकारों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंगुल से मुक्त होने का।
- पर, इस मुहिम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि भारत की जनता इन स्वदेशी टैक्नॉलजी वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स को कितनी जल्दी और तत्परता से अपनाती है।
- "स्वदेशी टैक" को भी जनता तभी स्वीकार करेगी, जब ये प्रोडक्ट्स, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले कमज़ोर साबित न हों।
- ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए, लगातार आर. एण्ड डी. पर भारी खर्च करना होगा तथा भारतीय कामगारों में "स्किल" (हुनर) भी किसी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में पोचा न पड़े तथा सरकार की नीतियों का पूर्ण सहयोग व प्रोत्साहन मिले इस "स्वदेशी टैक" को।

को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण मिसाल है।
अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ की राष्ट्रीय मुहिम मोदी की अपील को जन आंदोलन में बदलने की कोशिश कर रही है। इसी बीच, मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंकड इंसैटिव (पीएलआई) जैसी योजनाएँ स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को घरेलू तकनीकी समाधान विकसित करने और बढ़ाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन और इन्फ्रस्ट्रक्चर सम्बंधी मदद दे रही हैं।
भारत के पास स्वदेशी टैक के सपने को पूरा करने की मजबूत नींव मौजूद है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज की

प्रयागराज, 26 सितंबर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिख समुदाय से जुड़े विवादित बयान को लेकर दायर निगरानी याचिका के

- राहुल गांधी ने सिख सम्बंधी विवादित बयान पर एमपी-एमएलए कोर्ट में निगरानी याचिका स्वीकार किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी।

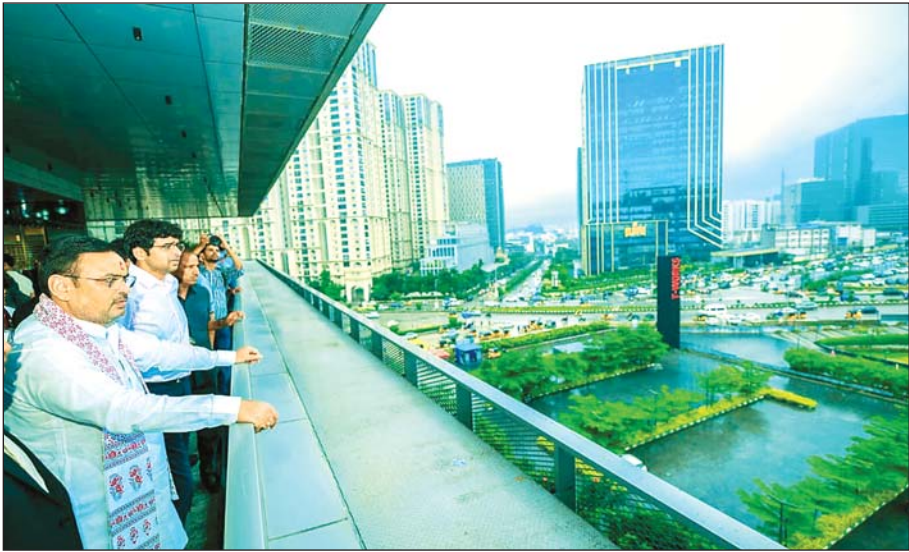
खिलाफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश समीर जैन की अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद तीन सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिस पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्य सरकार हर वर्ष ‘‘ प्रवासी राजस्थान सम्मान’’ देगी- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हैदराबाद में प्रवासी राजस्थान मीट में भाग लिया

जयपुर, 26 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हैदराबाद में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट में कहा कि दुनियाभर में रहने वाले प्रवासी

■ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष से 10 दिसम्बर को जयपुर में प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन किया जायेगा। प्रवासी राजस्थानियों के सामाजिक और व्यावसायिक प्रभावों को मजबूती देने के लिए एक विशेष विभाग गठित किया जायेगा।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को हैदराबाद में हाइटिक सिटी और आई टी हब का दौरा किया।

राजस्थानी जहां भी जाते हैं, वहाँ, अपनी संस्कृति और संस्कारों से राजस्थानी मिट्टी की खुशबू फैलाते हैं। उन्होंने प्रदेश में निवेश कर ‘विकसित राजस्थान’ के निर्माण में सहभागी बनने के लिए प्रवासी राजस्थानी का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि 10 दिसंबर को जयपुर में

प्रथम ‘‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’’ आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन हर वर्ष किया जाएगा और इस अवसर पर हर साल ‘‘प्रवासी राजस्थानी सम्मान’’ भी दिया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रवासी राजस्थानियों के सामाजिक और व्यावसायिक प्रयासों को मजबूती देने के लिए, एक विशेष विभाग गठित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में अतिरिक्त

जिला कलक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही, राजस्थान फाउंडेशन को सशक्त किया गया है। पिछले एक वर्ष में 14 नए चैप्टर खोले गए हैं और कुल 26 चैप्टर अब सक्रिय हैं। दुनिया के न्यूयॉर्क, लंदन, रियाद जैसे प्रमुख शहरों में फाउंडेशन के चैप्टर सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम निवेश की सीमा 100 करोड़ रुपये से घटाकर 50

करोड़, तथा रिपेस-2024 में 10 करोड़ कर दी गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सराहना की और कई उद्यमियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर राजस्थान फाउंडेशन की सदस्यता की शुरुआत भी की गई। कार्यक्रम में उद्योग राज्यमंत्री के के बिश्नोई, राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त मनीषा अरोड़ा, प्रवासी समुदाय के अनेक प्रतिनिधि व उद्यमी उपस्थित थे।

दशकों से अमेरिका...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) भी टैरिफ में बदलाव किया गया है। कुछ बड़ी दवा कंपनियाँ अपनी निवेश योजनाओं को यूरोप और ब्रिटेन में स्थित अपने पुराने ठिकानों से हटाकर अमेरिका की ओर ज्यादा केन्द्रित करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि भारत नए टैरिफ से प्रभावित हो सकता है, लेकिन इससे यूरोपीय और ब्रिटिश दवा कंपनियों के हितों को गहरा धक्का लग सकता है। उदाहरण के लिए, लंबे समय से स्थापित दवा कंपनी ग्लैक्सो

स्मिथक्लाइन बीचम अपने कुछ प्रस्तावित निवेश ब्रिटेन से हटाकर अमेरिका में स्थानांतरित कर रही है, ताकि टैरिफ के असर को कम किया जा सके। दवाओं के अलावा, राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के तहत, भारी टर्कों और कुछ फ़र्नीचर उत्पादों, जैसे किचन कैबिनेट्स और बाथरूम फिर्निचर्स पर भी टैरिफ लगाया गया है। फ़र्नीचर बनाने वाली अग्रणी स्वीडिश कंपनी की भी इन नए शुल्कों का सामना करना पड़ेगा।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कर रही है, लेकिन अब यह आशंका है कि भारत से निर्यात होने वाली कॉम्प्लेक्स जेनेरिक और स्पेशलिटी मेडिसिन्स भी इस दायरे में आ सकती हैं। हालांकि भारत की कई बड़ी कंपनियों के अमेरिका में पहले से उत्पादन केन्द्र मौजूद हैं, फिर भी इस नीति से उनका मुनाफा प्रभावित हो सकता है। अमेरिकी बाजार में पहले से ही कम मुनाफे पर काम कर रही भारतीय कंपनियों को इन शुल्कों को झेलना मुश्किल लग सकता है और अंततः

ट्रंप ने दवाओं...

इसकी लागत उपभोक्ताओं या बीमा कंपनियों पर डाल सकती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अमेरिकी उपभोक्ता कम कीमत वाली भारतीय जेनेरिक दवाओं पर निर्भर है। अगर इन पर भी शुल्क लागू हुआ, तो दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी महंगाई बढ़ेगी और संभवतः दवा की कमी भी हो सकती है ट्रंप पहले ही भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा चुके हैं, जिसमें रूस से तेल खरीद जारी रखने के लिए 25 प्रतिशत पेनल्टी टैक्स भी शामिल है।

इलाहाबाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) आज फैसला सुनाया गया। राहुल गांधी ने वाराणसी के स्पेशल जज, एमपी/एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। उन्होंने वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा निगरानी याचिका स्वीकार किए जाने को दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय से याचिका खारिज होने के बाद अब वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में निगरानी याचिका पर आगे की सुनवाई होगी। पिछली 21 जुलाई को वाराणसी एमपी/एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका को स्वीकार किया था जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शरण ली थी।

जस्टिस एस.पी. ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) फिलहाल जस्टिस एसपी शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। जस्टिस शर्मा 26 सितंबर, 2026 को रिटायर होंगे।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) बड़ी संख्या में इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और बहुत हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम पहले से ही प्रतिस्पर्धी घरेलू समाधान बना रहे हैं। जोहो और स्थानीय डिजिटल मैपिंग प्लेटफॉर्म जैसे सॉफ्टवेयर और सेवाओं के विकल्प यह साबित करते हैं कि देश व्यावहारिक विकल्प पेश करने में सक्षम है। विशाल घरेलू बाजार के साथ ये ताकतें तुरंत निर्यात पर निर्भर हुए स्थानीय नवाचार को बढ़ा बनाने का अवसर देती हैं। संभावनाओं के बावजूद कई बाधाएँ हैं। कई घरेलू तकनीकी उत्पाद फीचर्स, भरोसेमंदी और उपयोगकर्ता अनुभव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों से पीछे हैं, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए बदलाव मुश्किल हो जाता है। हार्डवेयर और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स में गहरी संरचनात्मक समस्याएँ हैं, क्योंकि भारत अभी भी आयातित पुर्जों और सीमित हार्ड-एंड विनिर्माण ढाँचे पर निर्भर है। अपूर्ति श्रृंखला की कमी,

आईटी मंत्री अश्विनी...

- ‘‘स्वदेशी टैक’’ को एक एडवान्टेज जरूर है, उनके समक्ष भारत का विशाल ‘‘डोमेस्टिक’’ मार्केट है और उन्हें विदेशी ग्राहकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- पर, यह भी सच है कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ दशकों से मार्केट में हैं तथा भारतीय ग्राहकों तक में उनके प्रति ब्राण्ड लॉयल्टी है।

असंगत इंटरनेट कनेक्टिविटी और ग्रामीण ढाँचे की कमियाँ अपनाने की प्रक्रिया को और जटिल बनाती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा भी दबाव बढ़ाती है। भारत को न केवल बराबरी करनी है बल्कि पहले से स्थापित बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला भी करना है, जिसके लिए लगातार रिसर्च और डवलपमेंट में निवेश करना नई प्रतिभा को जोड़ना व आधुनिक सुविधाओं का निर्माण करना होगा। उपभोक्ता व्यवहार- जिसे ब्रांड वफ़ादारी, कीमत की संवेदनशीलता और गुणवत्ता की धारणा प्रभावित करती है- भी एक चुनौती है। अगर मजबूत बौद्धिक संपदा सुरक्षा और

वैश्विक मानकों का पालन नहीं किया गया तो घरेलू विकल्पों के लिए भरोसा पाना कठिन होगा। स्वदेशी टैक पहले में बदलाव लाने की ताकत है।

मनमोहन सिंह के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के नेता राहुल गांधी तथा अन्य कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। खरगे ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर नमन करते हुए कहा कि देश में उन्होंने जो आर्थिक सुधार शुरू किए उनके कारण राष्ट्र आज तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है।

रॉनल्ड रीगन के...

कार और दोपहिया वाहनों की कीमतों में भारी कमी आई है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि ओटोमोबाइल निर्माताओं की बिक्री ज्यादा होगी। कम कीमत वाले सामानों, जैसे

- पर, यह भी सच है कि एक त्योहार का सीजन पर्याप्त नहीं है, देश की इकॉनमी को पार लगाने के लिए। जनता की डिमांड में कुछ स्थायित्व होना जरूरी है। अर्थशास्त्री यह भी आशा कर रहे हैं कि एक सफल सीजन में जो ‘‘डोमेस्टिक डिमांड’’ जागृत हुई है, उसकी लत लगेगी जनता को और भारत की इकॉनमी का चक्का चल निकलेगा, जैसा रीगन के समय हुआ था।

निर्यात का बड़ा भाग देश के भीतर ही अटका हुआ है, बजाय उन बाजारों में पहुँचने के, जहाँ के लिए इन्हें बनाया गया था। इन सामानों की बिक्री तभी होगी, जब घरेलू मांग मजबूत हो, ताकि सामान मैनुफैक्चर करने वालों पर अतिरिक्त माल का बोझ न पड़े। इसीलिए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे त्योहार मनाएँ, खर्च करें, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ी हुई मांग की मजबूत खुराक मिल सके। निश्चित रूप से इस समय जीएसटी दरों में की गई कटौती के कारण कीमतें घटने पर खरीदारों की तरफ से प्रतिक्रिया उत्साहपूर्ण होगी। उदाहरण के तौर पर, मोटर वाहनों की ऑन रोड कीमतों में कटौती हुई है। इसके परिणामस्वरूप,

विस्कूट पैकेट से लेकर दवाइयों तक, दरों में कटौती से भी मांग में उछाल आएगा और बिक्री में तेजी होगी। हालाँकि केवल एक त्योहार के मौसम की बिक्री लंबी अवधि में बड़ा असर नहीं डाल सकती। मांग में लगातार और स्थायी बढ़ोतरी के लिए मजबूत आधार होना चाहिए और यह भी जरूरी है कि मांग एक ऊँचे स्तर पर जाकर स्थिर हो। अर्थशास्त्र केवल त्योहारी सीजन की बिक्री और खुशगवार माहौल से नहीं चलता। इन प्रोत्साहनों को लंबे समय तक सफल बनाने के लिए मांग में वृद्धि को लंबे समय तक बनाए रखना होगा। यह काम केवल एक बार की रक कटौती से कहीं ज्यादा कठिन काम है। एक आशाजनक संकेत यह है कि

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप को सुविधानुसार पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर आने का भी सौहार्दपूर्ण निमंत्रण दिया।‘‘संघर्षविराम के पहले दिन से ही भारत यह कहता आया है कि यह पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारी ने ही अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क कर शत्रुता समाप्त करने और शांति स्थापित करने के लिये सम्पर्क किया था।

जब यह संदेश आया, तब तक भारत पहले ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में कई प्रमुख आतंकी ठिकानों को तबाह कर चुका था, जिनमें सैन्य लक्ष्य जैसे हैंगर, रडार, एंटी-एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म और एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं महंगा एडब्ल्यूएसीएस (एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) विमान शामिल थे, जो

जमीन पर मौजूद था। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने उन्हें फोन कर कहा था कि ‘‘पाकिस्तानी बातचीत के लिए तैयार हैं,’’ जिसके बाद पाकिस्तान के डायरेक्टर-जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन्स ने भारत से संपर्क किया। जयशंकर ने हाल ही में संसद में ‘‘ऑपरेशन सिंदूर’’ पर हुई बहस के दौरान कहा था, ‘‘22 अप्रैल (पहलगाम आतंकी हमला) और 17 जून (संघर्षविराम की घोषणा की तिथि) के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ट्रंप के बीच कोई बात नहीं हुई।’’ 2016 के उरी सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयरस्ट्राइक या अन्य पूर्व सैन्य अभियानों, जो ‘‘स्केल’’ तथा ‘‘स्कोप’’ के मामले में सीमित थे, तुलना में, ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी रूप से कहीं अधिक उन्नत, विस्तृत और भारत द्वारा अब तक की गई।

TRUE VALUE

खरीदे प्री-ओन्ड गाड़ी भरोसे के साथ, सिर्फ TRUE VALUE पर

CELEBRATING 60Lakh STORIES OF TRUST

यहाँ ऐप डाउनलोड करें। पूछताछ के लिए कॉल करें 1800 102 1800 | या जाएँ यहाँ www.marutisuzukitruuevalue.com

376 क्वालिटी चेक पॉइंट्स

वेरिफाइड कार हिस्ट्री*

1 साल तक की वारंटी और 3 फ्री सर्विस*

*नियम और शर्तें लागू। Verified Car History और Warranty केवल True Value प्रमाणित कारों पर लागू। निःशुल्क सेवा केवल श्रम शुल्क पर लागू है। वाहन पर काला शीशा प्रकाश प्रभाव के कारण होता है। छवियों का इस्तेमाल केवल उदाहरण मात्र है।

TRUE VALUE CERTIFIED

Jodhpur: Opposite Saran Nagar Gate A, Banar Road, Jodhpur, LMJ Services: 7230078225, 8094011141 | Plot No. C 62, Marudhara Industrial Area, Basni 1st Phase Saraswati Nagar, Jodhpur, Auric Motors Pvt. Ltd.: 7230043141, 7230043140 | Basni: 32-A, Heavy Industrial Area, Near F.C.I. Godowns, Jodhpur, Shri Krishna Auto Sales: 9799998584, 9829197669 | Pali: Near Veer Prabhu Garden, Jodhpur Road, Pali, LMJ Services: 7230026924. Pali: Near Veer Prabhu Garden, Jodhpur Road, Pali, LMJ Services: 7230026924.

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायवा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाऊस, हनुमान हवा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन् रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डोन्सिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डोन्सिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरु कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरु, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908